p>

Title: Issue regarding lifting of ban on 44 hydro electric power projects in Uttarakhand.

श्री अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे उत्तराखंड की एक गंभीर समस्या को उठाने का मौका दिया ।

मान्यवर, कुछ गलतफहमियों के कारण उत्तराखंड की 44 जल विद्युत योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा रोक दिया गया है । हमारे वहाँ गंगा, यमुना, टोंस, भागीरथी आदि सारी नदियों पर जल प्रोजेक्ट बने हुए हैं । पानी से जो बिजली पैदा होती है, उससे ही हम अपना राजस्व कमाते हैं । हमारी सरकार के पास राजस्व के अन्य कोई साधन नहीं हैं । हमारा बहुत छोटा सा राज्य है । इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवदेन है कि 44 जल विद्युत योजनाओं पर जो रोक लगी है, उसे तत्काल हटाया जाए । 3,062 करोड़ रुपये का निवेश अभी तक हो चुका है, 48 हजार करोड़ रुपये का निवेश अभी संभावित है । हमें 8,960 मिलियन यूनिट की हानि हो रही है । हमें 3,540 करोड़ रुपये सालाना राजस्व की हानि हो रही है । इसके अलावा 52 हजार रोजगार, जो हम लोगों को, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता था, उस रोजगार की भी हानि हो रही है । संभवत: सरकार को ऐसा कोई संदेशा आया है कि गंगा में पानी नहीं छोडा जाएगा । वर्ष 1917 में हरिद्वार में जो गंगा महासभा के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उसके आधार पर, वह एग्रीमेंट अंग्रेजों के साथ हुआ था, उसके आधार पर 1 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जाना अति आवश्यक था, परन्तु जो स्पेशल कमेटी अभी गई थी, उसके आधार पर 5 हजार क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जो देश के लिए भी पर्याप्त है । इसलिए मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जल विद्युत परियोजनाओं पर जो रोक लगी हुई है, उस रोक को तुरन्त हटाकर निर्माण प्रारम्भ कराया जाए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।